卐 श्री सदगुरू देवाय नम:卐 卐ओ३म्卐 卐 जय माता दी 卐
卐 सीताराम बाबा जी 卐卐जय बाबा की卐卐श्याम बाबा卐卐
卐 ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा!! 卐

उल्लंघ्य सिन्धो: सलिलं सलीलं,य:शोकवह्निं जनकात्मजाया: आदाय तेनैव ददाह लंकां,नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये

केन्द्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 26 ♦अंक 76 ♦पृष्ठ 8 ♦रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ♦सोमवार ♦22 दिसम्बर 2025 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

जनता की सहयोगी बनकर कार्य कर रही सरकार:धामी

मुख्यमंत्री ने सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारम्भ, जोरदार रोड शो के बाद जन-जन की सरकार कार्यक्रम में भी किया प्रतिभाग

अल्मोड़ा(उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हेमंवती नंदन बहुगुणा खेल मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का शुभारम्भ किया, जहाँ युवाओं और बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और समर्पण की भावना भी सिखाते हैं। भाजपा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है और खेल महोत्सव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने शारीरिक एवं मानसिक कौशल को निखारे और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। इसके बाद मुख्यमंत्री ताड़ीखेत पहुँचे और जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। (शेष पृष्ठ सात पर)

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ तहसील में गरजे ग्रामीण

रामनगर(उद संवाददाता)। ग्राम पूछडी में कुछ दिन पूर्व वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद से ही पीड़ित परिवार और विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि उनके पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भी कड़ाके की ठंड में परिवार अपने मासूम बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। सोमवार को पीड़ित परिवारों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसील में आयोजित एक दिवसीय धरने में भाग लेकर सरकार और वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया और इस पर रोक लगाने की मांग की। धरने को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस. लाल सहित कई लोगों का समर्थन मिला। धरना स्थल पर हुए सभा में वक्ताओं ने कहा कि अब उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है और वे न्यायालय की शरण लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का (शेष पृष्ठ सात पर)

स्कूल में घुसा भालू,छात्र को उठाया

चमोली(उद संवाददाता)। चमोली जिले के पोखरी में सोमवार सुबह एक खौफनाक घटना हुई जब जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में कक्षा छह के छात्र आरव को स्कूल परिसर से भालू ने उठा लिया। गनीमत रही कि शिक्षकों और अन्य बच्चों ने तत्परता और साहस दिखाते हुए आरव की जान बचाई। बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकाला गया, लेकिन उसके शरीर पर भालू के नाखूनों के निशान पाए गए। घटना के समय स्कूल में अफरातफरी मच गई। भालू ने कक्षा का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। अपने साथी पर हमला होते देख कई बच्चों और शिक्षकों ने हिम्मत दिखाई और दौड़कर आरव को बचाया। इस साहसिक प्रयास के बावजूद स्कूल में भय का माहौल बन गया और कई बच्चे रोते-बिलखते नजर आए। दो दिन पहले इसी स्कूल के एक छात्र पर रास्ते में भालू ने हमला किया था। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में भालू का प्रवेश चिंता का विषय बन गया है। उधर जौलीग्रांट के थानो वन रेंज के पहाड़ी क्षेत्रों में भालू के आतंक को देखते हुए वन प्रहरियों के साथ बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। हाल ही में गडूल पंचायत के कमेठ (सोड) गांव में दो भालुओं ने (शेष पृष्ठ सात पर)

पूर्व प्रधान ने तहसील में शुरू किया बेमियादी धरना

नानकमत्ता(उद संवाददाता)। पंचायत चुनाव में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की आपत्ति लगने और प्रधानी का पर्चा निरस्त होने के बाद ग्राम सरोंजा के पूर्व प्रधान बजिंदर सिंह ने तहसील परिसर में अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पूर्व प्रधान बजिंदर सिंह का आरोप है कि पिछले पंचायत चुनाव में उनके विपक्षी ने उन पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उनका प्रधान पद का पर्चा निरस्त कर दिया गया। बजिंदर सिंह ने तहसील प्रशासन से अपने कब्जे संबंधी जानकारी लिखित और लोक सूचना अधिकार के तहत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और इसे न्यायालय में विचाराधीन बताया। पूर्व प्रधान ने कहा कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक तहसील प्रशासन उन्हें लिखित में स्पष्ट नहीं करता कि उनका सरकारी जमीन पर कब्जा है या नहीं। उनका कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से स्पष्टता नहीं दी गई। पूर्व प्रधान ने चेतावनी(शेष पृष्ठ सात पर)

चलती कार में लगी आग,पांच खिलाड़ी बाल-बाल बचे

देहरादून (उद संवाददाता)।रिस्पना पुल पर सोमवार सुबह अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में पांच युवक सवार थे, जो छिदरवाला की तरफ से आ रहे थे। सभी युवक हल्द्वानी के क्रिकेटर बताए जा रहे हैं और देहरादून में टूर्नामेंट खेलने गए थे। घटना थाना नेहरू कॉलोनी इलाके की है। जानकारी के अनुसार, चलते कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। युवक तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने वाहन छोड़ा, गाड़ी पूरी तरह आग के गोले में बदल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुशलता के साथ आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि सभी पांच युवक सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट या जान-हानि नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि पांचों युवक आयुष एकेडमी छिदरवाला से मैच खेलकर लौट रहे थे। इस हादसे के कारण गाड़ी में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की मानव हानि टल गई।

‘संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन’ की दिशा में ‘सीएम धामी’ का बड़ा कदम

उत्तराखंड के स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भगवत गीता,मुख्यमंत्री धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार के इस कदम की दी जानकारी

-अर्श-

देहरादून। देश में सबसे पहले एनआरसी लागू करने, उत्तराखंड में अत्यंत सख्त धर्मांतरण कानून बनाने, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कठोर कानून निर्माण सहित तमाम बड़े कार्य करने के बाद ,अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गुजरे रविवार को मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि “ हमारी सरकार ने राज्य के स्कूलों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके ”। उन्होंने विश्वास जताया कि गीता के उपदेश बच्चों में आत्म विश्वास, कर्तव्यबोध और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जीवन के हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान तथा व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है। जिसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा, तनाव प्रबंधन एवं विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क निहित हैं। लिहाजा, श्रीमद् भगवत गीता विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसारशिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए यह निर्देश पहले ही जारी कर दिया किया था कि वे समय-समय पर भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करें तथा छात्र-छात्राओं को जानकारी दें कि श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत किस तरह से मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। साथ ही छात्र-छात्राओं को यह भी अवगत कराया जाए कि श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उपदेश सांख्य, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, व्यवहार विज्ञान एवं नैतिक दर्शन पर आधारित हैं, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ। मुकुल कुमार सती के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या की रुप रेखा में शामिल (शेष पृष्ठ सात पर)

कृषि भूमि की बिगड़ती सेहत और किसान

23 दिसम्बर किसान दिवस पर विशेष

दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी वन क्षरण, अत्याधिक कृषि गतिविधियों से भूमि की नमी घटने और उसकी उर्वरता कम होने की समस्या से जूझ रहा है। इन कारणों के चलते भारत की 30 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि की सेहत बिगड़ गई है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास से कृषि भूमि नष्ट हो रही है। वहीं उद्योग, बिजली और सिंचाई व पेयजल के लिए बड़े बांधों के अस्तित्व में आ जाने के कारण दलदली भूमि भी बढ़ रही हैं।यह समस्या मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में सर्वाधिक होने के साथ, इन्हीं राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। इससे 72000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। क्षरण और भूमि के मरुस्थलीकरण से हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 प्रतिशत और फसल की पैदावार में भी कमी आई है। इधर खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जीएम फसलों की पैदावार ने भी खेतों की सेहत बिगाड़ने का काम बड़ी मात्रा में किया है।नतीजतन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव भी गहरा गए हैं। वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण की समस्या के समाधान के लिए 450 अरब डॉलर का वार्षिक खर्च आएगा। यदि इसमें सुधार जल्दी नहीं किया गया तो विश्व में 3.2 अरब लोगों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। भारत के लिए यह समस्या इसलिए विकराल है, क्योंकि दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या भारत में बसती है, जबकि दुनिया की कुल भूमि का भारत के पास महज 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही है। साफ है, उपजाऊ जमीन का बंजर भूमि में बदलना चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी समिति द्वारा अगस्त-2019 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 23 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत भूमि के क्षरण का है। चुनांचे निकट भविष्य में भूमि में व्यापक सुधार नहीं हुए तो यह समस्या एक प्राकृतिक आपदा में बदलती चली जाएगी। यह विडंबना ही है कि भारत में रोटी और रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन बनी भूमि की गुणवत्ता अथवा उसकी बिगड़ती सेहत को जांचने का अब तक कोई राष्ट्रव्यापी पैमाना नहीं है। जबकि देश की कुल आबादी में से सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि और प्राकृतिक संपदा से रोजी-रोटी जुटाती है। भूमि की उर्वरता और क्षरण को लेकर टुकड़ों में तो आकलन आते रहते हैं, लेकिन इस स्थिति की वास्तविक हालत का खुलासा करने वाला कोई एक मानचित्र देश की जनता के सामने पेश नहीं किया गया। हालांकि अशासकीय स्तर पर इस मांग की आपूर्ति अहमदाबाद की संस्था 'स्पेस एप्लिकेशन सेंटर' ने सत्रह अन्य इसी काम से जुड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर की है। जमीन की सेहत से जुड़ा यह शोध बताता है कि आधुनिक व औद्योगिक विकास, जल व वायु प्रदूषण और कृषि भूमि में खाद व कीटनाशकों के बढ़ते चलन ने किस तरह से उपयोगी भूमि को रेगिस्तान में तब्दील करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 'स्पेस एप्लिकेशन सेंटर' द्वारा किए शोध के मुताबिक राजस्थान का 21.77 प्रतिशत, जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख का 12.79 और गुजरात में 12.72 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान में बदल चुका है। मध्यप्रदेश में चंबल के बीहड़ पिछले 60 साल में 45 प्रतिशत बढ़े हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर-प्रदेश व मध्यप्रदेश में बुंदेलखण्ड क्षेत्र की कृषि का अनावृष्टि के कारण तेजी से क्षरण हो रहा है। वहीं भू-जल के बेतहाशा दोहन और अल्पवर्षा के चलते खेतों में दस सेंटीमीटर नीचे एक ऐसी कठोर परत बनती जा रही है, जो कालांतर में फसल की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करेगी। रेगिस्तान के विस्तार की तह में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का चक्र तो है ही 1999 के बाद से मानसून की दगाबाजी ने उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल देने का काम किया है। इन्हीं वजहों से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र भूमिक्षरण के प्रभाव में आए जंगलों का विनाश, चरनोई की भूमि को कृषि व आवासीय भूमि में तब्दील करना और एक तरह की फसल पैदा करने के बढ़ते चलन से भूमि की सेहत बिगड़ी है। कुछ ऐसी ही वजहों के चलते बर्फीली वादियों से लेकर घने वनों वाले क्षेत्र भी फैलते रेगिस्तान की गिरफ्त में आ गए हैं। जिस हरित क्रांति के बूते पंजाब को भारत का अनाज के अटूट भंडार का दर्जा हासिल हुआ था, वही पंजाब आज रासायनिक खादों का बेतहाशा उपयोग करने के कारण बड़ी तादात में अपनी कृषि भूमि बरबाद कर चुका है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का 1.5 प्रतिशत भाग पंजाब के हिस्से में है। जबकि देश में कीटनाशकों की कुल खपत का 18 फीसदी उपयोग पंजाब के किसान करते हैं। इसी तरह पंजाब के मालवा क्षेत्र का कपास क्षेत्र पूरे पंजाब का केवल 15 फीसदी है, जबकि यहां पंजाब के कुल कीटनाशकों की खपत 70 फीसदी है। पंजाब के मालवा का क्षेत्र देश के कुल भू-भाग का मात्र 0.5 भाग है, जबकि यहां देश में कुल खपत होने वाले कीटनाशकों की 10 फीसदी खपत होती है। जिस भांखड़ा नांगल बांध को हम पंजाब की उन्नत खेती का आधार मानते हैं, इस बांध से जल रिसाब के चलते पंजाब की अब तक ढ़ाई लाख हेक्टेयर कृषि भूमि दलदल में बदल चुकी है। यही नहीं कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने यहां कैंसर की बीमारी को बड़ी आबादी में परोस दिया है। कृषि के आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण ने भी भूमि की सेहत को बिगाड़ने का काम किया है। इस बाबत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किए गए एक शोध के मुताबिक इस अंचल की भूमि में दो तरह के विकार पैदा हुए हैं। एक कृषि भूमि की सतह में दस सेंटीमीटर नीचे एक कठोर परत (हार्ड-लेयर) बन गई है। दूसरे, भू-गर्भ में करीब एक सौ मीटर की गहराई पर पानी से भरी रहने वाली जगह (पोर-स्पेस) रिक्त पड़ी है। क्षेत्रीय पर्यावरण में आए ये परिवर्तन भू-गर्भीय अथवा सतह पर भूकंप जैसी हलचल की वजह भी बन सकते हैं। डिस्कवरी चौनल द्वारा इस क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन के प्रस्तुतीकरण ने भी दावा किया है कि चंबल व ग्वालियर अंचल में तेजी से रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। इस अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा परंपरागत खेती को नकारने से हुआ। पहले हलों से खेतों की जुताई होती थी लेकिन अब हैरो, कल्टीवेटर और प्लाऊ जैसे उपकरणों से हो रही है। ये जमीन को आठ से बारह सेंटीमीटर तक गहरा जोत कर भूमि की ऊपरी परत को उधेड़ कर पलट देते हैं। नतीजतन मिट्टी सूख कर शुष्क होती जा रही है और वहीं इसके नीचे की परत कठोर। यह परत अब इतनी कठोर हो गई है कि खेतों की मिट्टी का आनुपातिक कुदरती जैविक समीकरण ही गड़बड़ा गया है। इधर चंबल क्षेत्र में भूमि के लगातार बिगड़ रहे पर्यावरण ने बीहड़ो के विस्तार का ऐसा भयावह सिलसिला जारी रखा हुआ है, जो गांव के गांव लीलता जा रहा है। इस अंचल के भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में हर साल पन्द्रह सौ एकड़ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है। इन जिलों की कुल भूमि का 25 फीसदी हिस्सा बीहड़ों का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बीहड़ों का विस्तार है। इन तीनों जिलों के क्षेत्र में जितनी भी छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, वे जैसे बीहड़ों के निर्माण के लिए अभिषप्त हैं। चंबल में 80 हजार, कुआंरी में 75, आसन में 2036, सीप में 1100, बैसाली में 1000, कूनों में 8072, पार्वती में 700, सांक में 2122 और सिंध में 2032 हेक्टेयर बीहड़ हैं। बीते दस सालों में करीब 45 प्रतिशत बीहड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन बीहड़ों का जिस गति से विस्तार हो रहा है, उसके मुताबिक 2050 तक 55 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बीहड़ों में तब्दील हो जाएगी। नतीजतन करीब दो हजार आबाद गांव बीहड़ लील लेंगे। इन बीहड़ों का विस्तार एक बड़ी आबादी के लिए विस्थापन का संकट पैदा करेगा ? जमीन की सेहत अब प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानव उत्सर्जित कारणों से ज्यादा बिगड़ रही है। पहले भूमि का उपयोग रहवास और कृषि कार्यों के लिए होता था, लेकिन अब औद्योगीकरण, शहरीकरण, बड़े बांध और बढ़ती आबादी के दबाव भी भूमि को संकट में डाल रहे हैं। जमीन का खनन करके जहां उसे छलनी बनाया जा रहा है, वहीं जंगलों का विनाश करके जमीन को बंजर बनाए जाने का सिलसिला जारी है। जमीन की सतह पर ज्यादा फसल उपजाने का दबाव है तो भू-गर्भ से जल, तेल व गैसों के अंधाधुंध दोहन के हालात भी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के जो नलकूप जैसे आधुनिक संसाधन हरित क्रांति के उपाय साबित हुए थे, वही उपाय खेतों में पानी ज्यादा मात्रा में छोड़े जाने के कारण कृषि भूमि को क्षारीय भूमि में बदलने के कारक सिद्ध हो रहे हैं। दरअसल अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की सेहत अलग-अलग कारणों से प्रभावित हो रही है, जिसकी देशव्यापी पड़ताल अब तक नहीं हुई है। धरती की बिगड़ती इस सेहत को मानचित्र पर लाना जरुरी है।

प्रमोद भार्गव ,लेखक, साहित्यकार व वरिष्ठ पत्रकार हैं ।

बीडीओ ताकुला और एई समेत चार अफसरों पर गबन की प्राथमिकी, फर्जी दस्तखत से हड़प ली रकम

हल्द्वानी। अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित ग्राम तीताकोट में बिना सड़क निर्माण किए 60 हजार रुपये और ग्राम शैल में शौचालय बनवाए बिना 50 हजार रुपये का फर्जी भुगतान लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर सोमेश्वर कोतवाली में बीडीओ ताकुला, लघु सिंचाई ऊधमसिंह नगर के सहायक अभियंता सहित चार अफसरों के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज हुई है। तहरीर देने वाले तीताकोट के तत्कालीन प्रधान सुधीर कुमार ने पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से भी गुहार लगाई थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सीजेएम अल्मोड़ा की कोर्ट में दाखिल परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। इन सभी पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराएं लगी हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर कोतवाली अंतर्गत ग्राम तीताकोट के तत्कालीन प्रधान सुधीर कुमार ने दाखिल परिवाद में बताया कि वह 2018 में प्रधान थे। उनकी ग्राम पंचायत में बिना उनकी जानकारी के 60 हजार रुपये सीसी निर्माण कार्य मद में भुगतान किया गया। जानकारी होने पर जब खंड विकास अधिकारी ताकुला और बीडीओ कार्यालय में सम्बद्ध ऊधमसिंह नगर के लघु सिंचाई विभाग के एई ने कार्यादेश नहीं दिया। काम कराया नहीं गया और इसका भुगतान उनके द्वारा ले लिया गया। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ने फर्जी पत्र दिया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। धनराशि भुगतान, कार्य पूर्ण को ग्राम पंचायत के परिसंपत्ति में अंकित भी करा दिया गया। मेरे फर्जी हस्ताक्षर और मोहर का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार ग्राम शैल में भी तत्कालीन प्रधान शेरराम के फर्जी हस्ताक्षर ओर मोहर का प्रयोग कर बिना शौचालय निर्माण के 50 हजार रुपये का भुगतान लिया गया। एसपी अल्मोड़ा, कमिश्नर कुमाऊं और सूचना आयुक्त के पास भी शिकायती पत्र भेजा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। सीजेएम के आदेश के बाद सोमेश्वर कोतवाली में बीडीओ ताकुला किशन राम वर्मा, एई बीडीओ आफिस ताकुला (वर्तमान तैनाती लघु सिंचाई ऊधमसिंह नगर के एई) जीवन चंद्र जोशी, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वर्तमान तैनाती विकास कपकोट) बागेश्वर एसएस चौडिया और सहायक समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कोहली के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज बनाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

दो मंजिला मकान में लगी आग, बच्ची की जलकर मौत

उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में बड़कोट क्षेत्र के कोटि गगटाड़ी निवासी शैलेन्द्र चौहान के लसरी नामे तोक स्थित दो मंजिला आवासीय मकान में रविवार की शाम अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में मन बहादुर नेपाली मूल की ढाई माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि मकान में रखा सारा घरेलू सामान व भवन जल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि मकान में रह रहे लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले लेकिन मासूम बच्ची आग की चपेट में आ गई और उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।आग लगने की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार खजान असवाल के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर नुकसान के आकलन एवं घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन न होने के कारण आगजनी की घटनाओं में नुकसान अधिक हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर अत्याचार के विरोध में किया प्रदर्शन, पुतला फूंका

शक्तिफार्म(उद संवाददाता)। बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार के सदस्य के साथ हुई जघन्य घटना के विरोध में शक्तिफार्म क्षेत्र में आक्रोश का उबाल देखने को मिला। श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचन्द्र राय के नेतृत्व में समाजसेवियों एवं हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तथा घटना के दोषियों के पुतले बनाकर श्मशान घाट में प्रतीकात्मक रूप से उनका दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार एवं विश्व के सभी मानवाधिकार संगठनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को तत्काल रोकने, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। इस प्रदर्शन के माध्यम से वैश्विक समुदाय का ध्यान बांग्लादेश में लगातार सामने आ रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कथा वाचक आचार्य रामचन्द्र राय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाएं मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाओं के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी। आचार्य राय ने भारत सरकार से इस विषय पर कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस दबाव नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगना कठिन है। भारत द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही विभिन्न प्रकार की सहायता पर पुनर्विचार किए जाने की भी उन्होंने मांग की। उन्होंने बताया कि श्मशान घाट में पुतलों का दहन एक प्रतीकात्मक प्रयास है, ताकि विश्व भर के हिंदूवादी संगठन और मानवाधिकार संस्थाएं जागरूक होकर पीड़ितों के समर्थन में आगे आएं। इस विरोध प्रदर्शन में अभिषेक सरकार, राजू बर्मन, आनंद राय, त्रिनाथ बिस्वास, उत्तम कुमार, सुब्रत राय, अनिमेष सरकार, राम गोपाल सरकार, सुजीत गोल्डर, केशव मंगल कुमार सरकार, धीरज कुमार, गंगाधर बिस्वास, प्रशांत विश्वास, हरिप्रसाद मंडल, सुषेण हालदार, भोपाल राय, त्रिनाथ मंडल, सत्यजीत कुमार मंडल, मनोज बर्मन, विजय बर्मन, शंकर मजूमदार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

बेरोजगारी से त्रस्त जनता मांग रही परिवर्तन : यशपाल

सितारगंज। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सितारगंज में कांग्रेसजनों से संवाद किया। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाने तथा वर्ष 2027 में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया।शनिवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का सितारगंज पहुंचे। यहां कांग्रेसजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने सितारगंज के औद्योगिक विकास व कांग्रेस सरकार में किए विकास कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया।उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा कि किसान, मजदूर, छात्र, युवा समेत समाज का हर वर्ग परेशान है। महंगाई से त्रस्त जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहां कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरताज अहमद, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष करन जंग, ब्लॉक

अध्यक्ष हरप्रीत सिंह हैप्पी, मुख्तयार अंसारी, प्रधान दिलबाग सिंह उपस्थित रहेंइधर, देर सायं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मण्डी के पूर्व चेयरमैन हरपाल सिंह के आवास पहुंचे। वहां हरपाल सिंह की माता जसवीर कौर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने पति गुरुमुख सिंह, पुत्र हरपाल सिंह व गुरदेव सिंह से मिलकर संवेदना व्यक्त की। यहां किसान नेता लक्खा सिंह, प्रगट सिंह, पूर्व पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे, सरफराज अहमद राजू, अमरेश सिंह, शमशेर सिंह, गुरप्रीत सिंह औजला, बलविंदर सिंह उपस्थित रहें।

अमीरों के अतिक्रमण के चलते काशीपुर में आम जनता परेशान

सूचना अधिकार से खुलासा: मुरादाबाद रोड पर पी.डब्लू.डी. को मिले 98 व्यक्तियों के अतिक्रमण

काशीपुर। अतिक्रमण व जाम की समस्या का सारा दोष गरीब रिक्शा तथा पथ विक्रेताओं (फड़ व खोखे वाले) के सर मढ़ दिया जाता हैं लेकिन वास्तविकता में अमीरों के अतिक्रमण के चलते काशीपुर में आम जनता परेशान हैं। काशीपुर में अस्पतालों, स्थायी दुकानदारों तथा शोरूम तथा चौपहिया तथा भारी वाहनों की अवैध पार्किंग से सरकारी सड़कों पर अमीरों ने अतिक्रमण कर रखा हैं जिसके कारण अन्य अतिक्रमणों को बढ़ावा मिल रहा हैं तथा जाम की समस्या से लोग बेहाल है। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत पी.डब्लू.डी. द्वारा नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी सूचना से हुआ। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने पी.डब्लू.डी. के लोक सूचना अधिकारी से काशीपुर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर मार्ग की चौड़ाई तथा अतिक्रमण की सूचना चाही। इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी मिंाण खण्ड लोक निर्माण विभाग काशीपुर इंजी0 नेहा शर्मा ने अपने पत्रांक 100 के साथ सूचना उपलब्ध करायी है।श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार काशीपुर नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के भाग (मुरादाबाद व बाजपुर रोड) की सड़क की भूमि की चौड़ाई के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों के चकबन्दी नक्शों की फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी है। इसके अनुसार ग्राम सरवरखेड़ा में जसपुर रोड पर किमी.154 में मार्ग भूमि की चौडाई 27 से 30 मीटर, किमी 155 में 36 से 45 मीटर ग्राम महेशपुरा में जसपुर रोड पर किमी 155 में 36 से 45 मीटर चौड़ाई है। जसपुर बस अड्डा क्षेत्र में 45 मीटर, महेशपुरा की पुलिया के पास 42 मीटर तथा टांडा मोड़ से चौराहे तक 16 से 18 मीटर तथा ग्राम जसपुर खुर्द में आर.ओ.बी से द्रोणा सागर नहर तक 21 में 27 मीटर, ग्राम टांडा उज्जैन में चौती चौराहे क्षेत्र से महादेव नहर तक 24 से 27 मीटर दर्शायी गयी है।श्री नदीम को उपलब्ध अतिक्रमण कारियों की सूचना के अनुसार मुरादाबाद रोड पर (किमी. 156 से किमी.159 में) पी.डब्लू.डी. को 98 अतिक्रमण मिले है। अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमणों को समय-समय पर हटाया जाता है। इसमें स्थायी दुकानदारों व दुकानों के मालिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों, स्कैन सेंटरों, आदि के अतिक्रमण शामिल है।।46 कानूनी जागरूकता पुस्तकों के लेखक कानून के जानकार तथा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट का मानना हैं कि अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत बिना किसी कानूनी कार्यवाही तथा अभिलेखों के गलत तरीके से अतिक्रमण हटाया जाता है उसके अगले दिन ही अतिक्रमणकारियों द्वारा पुन: अतिक्रमण कर लिया जाता है। अतिक्रमणकारियों ने जहां अपने चौपहिया तथा भारी वाहनों की पार्किंग स्थायी रूप से सरकारी सड़कों को बना रखा है, वहीं दुकानदारों ने अपने शोरूम, वर्कशाप तथा प्रचार कार्यों के लिये भी सड़क की भूमि तथा फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है। इस समस्या से तब ही छुटकारा पाया जा सकता है जब इसके लिये जिम्मेदार विभागों पी.डब्लू.डी, नगर निगम तथा पुलिस तथा परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी कर्तव्यों का सही रूप से पालन करें और अतिक्रमण होते ही रोका जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्था में फायदे में अतिक्रमणकारी ही रहता है और नुकसान सदैव सड़कों का प्रयोग करने वाले आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। इसका खमियाजा गरीब फड़, खोखे वाले पथ विक्रेताओं तथा रिक्शा चालकों को भुगतना पड़ता हैं। उन्हें जिम्मेदार मानते हुये पथ विक्रेता अधिनियम 2014 तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध अवैध रूप से इन पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की जाती है। जबकि इनके प्रयोग की जगह पर कब्जा दुकानें आगे बढ़ाकर, समान आदि सड़क पर रखकर व पार्किंग बनाकर तथा भारी वाहनों को खड़ा कराकर किया जाता है। कई बार तो अपनी दुकान के आगे फड़ आदि लगवाने के लिये इन अमीर अतिग्रमणकारियों द्वारा किराया तक वसूले जाने के मामले प्रकाश में आये है।श्री नदीम ने बताया कि वास्तविक में अतिक्रमण रोकने सम्बन्धी कानून काफी मजबूत हैं लेकिन सम्बन्धित, अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी का सही से पालन न करने से यह समस्या इतनी विकराल होती जाती हैं। विभिन्न मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण करवाकर तथा इनसे मिलीभगत करके अतिक्रमण कारियों को लाभ पहुंचाया जाता है। इसके लिये सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी के विरूद्ध सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन तथा ड्यूटी में लापरवाही व अवैध लाभ पहुंचाने के लिये सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करके निलम्बन व बर्खास्तगी, निन्दा तथा डिमोशन तक किया जा सकता है। अस्थाई, संविदा तथा आडटसोर्स कर्मचारियों को तो सीधे सेवा से ही हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिली भगत करके अतिक्रमणकारियों को छूट देने वाले व अतिक्रमण कराने वाले कार्मिकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के मुकदमें सहित विभिन्न अपराधों के मुकदमें दर्ज हो सकते हैं।श्री नदीम ने बताया यदि नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा नियमानुसार प्रति दिन नाले-नालियों तथा सड़क की सफाई की जाये तो इसमे रूकावट बनने वाला अतिक्रमण उसी समय हटा दिया जायेगा और होगा ही नहीं। इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिनियम उत्तराखंड कूड़ा फेंकना व थूकना निषेध अधिनियम 2016 तथा उत्तराखंड सम्बन्धित विरूपण अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पी.डब्लू.डी. का मार्ग होने पर सम्बन्धित कर्मचारियों की ड्यूटी इसकी भूमि अतिक्रमण मुक्त रखना है। इसके लिये उनके द्वारा अतिक्रमण हटवाने के अतिरिक्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि व यातायात) अधिनियम 2002 तथा उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा अधि नियम 2014 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। सभी सार्वजनिक सड़कों की सुरक्षा तथा अवरोध मुक्त रखना पुलिस कर्मियों का भी कर्तव्य है। पुलिस कर्मियों के द्वारा जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 171 व 172 के अन्तर्गत संबंधित अतिक्रमण सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिये गिरफ्तारी तक की जा सकती हैं, साथ ही सार्वजनिक सड़क को नुकसान पहुंचाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(ख) तथा सार्वजनिक जल निकासी को नुकसान पहुंचाने पर धारा 326(ग) का पांच वर्ष तक की सजा से दण्डनीय धारा 126(2) का सदोष अवरोध अपराध ों के मुकदमें सहित विभिन्न अपराधों के मुकदमें दर्ज कराये जा सकते हैं। अवैध रूप से सड़क को पार्किंग बनाकर वाहन खड़े करने पर आर.टी.ओ. तथा उसके अधीनस्थ परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये जा सकते है।

ट्रांजिट कैम्प में ठुकराल ने किया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ

रूद्रपुर। लालबहादुर शास्त्री यंग क्लब की ओर से ट्रांजिट कैंप फुटबॉल मैदान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पीएसी और रूद्रपुर की टीम के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने शानदार तालमेल, गति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह युवाओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखने के लिए खेलों का विशेष महत्व है। ऐसे टूर्नामेंट युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने का अवसर प्रदान करते हैं। ठुकराल ने कहा कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में लगातार खेल गतिविधियों का आयोजन होना गर्व की बात है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि लालबहादुर शास्त्री यंग क्लब जैसे संगठन युवाओं को मंच प्रदान कर समाज के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से राज्य और देश स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी निकलकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खेल भावना से खेला गया हर मैच जीत-हार से ऊपर होता है और खिलाड़ियों को हमेशा खेल को खेल की तरह लेते हुए आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर ट्रांजिट कैंप व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संजीव गुप्ता, मानस बैरागी, आनंद शर्मा, ब्रजेन मंडल, शुभम स्वर्णकार, सुमित गुप्ता, प्रकाश अधिकारी, रोहित अधिकारी, सुमित निषाद, मोहित निषाद, हर्षित बोरा, सोहन, क्रिश यादव, मुकेश यादव, निखिल, राहुल, राजा, कुलदीप सिंह, अमन यादव, रोहित सिंह, आयुष यादव, चंदन, मुनि, हर्षित, मोहित निक्कू, तुषार, सुमित सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, खिलाड़ी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

गुलरभोज में दो नए पार्क और फुटपाथ का शिलान्यास

गुलरभोज (उद संवाददाता)।नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने वार्ड नंबर 3 में दो नए पार्क और टाइल्स वाले फुटपाथ का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सतीश चुग ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में आईटीआई के समीप तराई के संस्थापक भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और बुक्स समाज के आराध्याय राजा जगदेव के नाम से राज्य वित्त मद से दो पार्क और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 42 लाख रुपए है। शिलान्यास कार्यक्रम में जनजाति आयोग के सदस्य बाबू सिंह तोमर, विजय शर्मा, गोविंद राजभर, भूपेंद्र आर्य, इंदर सिंह राठौड़, राजू सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण

हल्द्वानी(उद संवाददाता)।राष्ट्रीय राजमार्ग 87 काठगोदाम-नैनीताल चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मूल्यांकन, सत्यापन एवं अंश निर्धारण के संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा रविवार को राजस्व, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि वर्तमान में इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत भूमि अंश निर्धारण के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वे पूर्ण होने के पश्चात प्रतिकर (मुआवजा) निर्धारण कर उसके वितरण की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त प्रक्रियाएं शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण की जाएं। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग श्री प्रमोद सुयाल, तहसीलदार नैनीताल श्री अक्षय भट्ट, राजस्व निरीक्षक एवं उप निरीक्षक, वन विभाग एवं उद्यान विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा कंसल्टेंसी कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अभ्यास वर्ग में संगठन की भूमिका पर की विस्तृत चर्चा

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड का दो दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग 20 एवं 21 दिसंबर को स्वामी नारायण आश्रम, मुनि की रेती, ऋषिकेश में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा संगठन मंत्र के सामूहिक गायन के साथ हुआ।अभ्यास वर्ग में कुल छ: सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र में पदाधिकारियों का परिचय एवं संगठन की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र बहुगुणा द्वारा व्रत निवेदन लिया गया। द्वितीय सत्र में स्वामी नारायण आश्रम के स्वामी सुनील भगत का मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्राप्त हुआ।देहरादून महानगर अध्यक्ष आलोक घिल्डियाल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं साइबर क्राइम पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सुरेश आर्य ने रोजगार सृजन आयाम पर अपने विचार रखे। विधि आयाम पर अमित भट्ट विधि प्रमुख ने, पर्यावरण आयाम पर कांति बल्लभ जोशी ने, महिला जागरण पर श्रीमती सुभाषिनी द्विवेदी द्वारा विषय प्रस्तुत किए गए।प्रचार आयाम के अंतर्गत डॉ. भूपेंद्र गंगवार ने संगठन के प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने कार्यकर्ता विषय पर प्रेरक उद्बोधन दिया। क्रियात्मक संबोधन में प्रांतीय सचिव राजपाल एवं राजपाल नेगी ने मार्गदर्शन किया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री लाखन सिंह ने अभ्यास वर्ग की भूमिका एवं आवश्यकता तथा अभ्यास वर्ग क्यों के बारे मे विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए, पूर्व विभाग प्रचारक कल्याण ने संगठन की मूल भावना एवं रीति नीति से सभी को अवगत कराया। डॉ मनोज रावत उत्तराखंड संगठन मंत्री ने सभी उपस्थित सदस्यों का अतिथियों का परिचय कराते हुए उत्तराखंड में संगठन की भूमिका पर अपनी बात रखी। अंतिम सत्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश ने प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन देते हुए अभ्यास वर्ग से प्राप्त सीखों को व्यवहार में उतारने पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रांत अध्यक्ष विनोद नौटियाल ने अध्यक्षीय संबोधन एवं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रांतीय अभ्यास वर्ग में उत्तराखंड के राज्य के सह सचिव राजेश मंजखोला, कु. प्रीति धीर, दीपक अंथवाल, चिरंजीव अवस्थी, शिवेन्द्र और विभिन्न जनपदों से आए कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता रही। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई।

कंस के कारागार में लिया भगवान कृष्ण ने जन्म

श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सुनने पहुंच रहे सैकड़ों श्रद्धालु

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन पूज्य स्वामी पद्मनारायणाचार्य महाराज जी ने बताया कि आज की कथा में मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु के अवतार, श्रीकृष्ण के जन्म की का वर्णन है, जहाँ कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में रखा गया था और भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात में कृष्ण का जन्म हुआ, जिसे बाद में गोकुल में नंद और यशोदा ने पाला, और वे कंस का वध कर धर्म की स्थापना के लिए बड़े हुए। उन्होंने कहा मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अपने पिता को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया और अत्यंत क्रूर हो गया। उसने अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद एक आकाशवाणी सुनी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा, जिससे डरकर उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उन्होंने कहा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि (जन्माष्टमी) को मध्यरात्रि में, जब पहरेदार सो रहे थे, देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र के रूप में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। स्वामी पद्मनारायणाचार्य महाराज जी ने कथा सुनाते हुए बताया कि जन्म लेते ही वासुदेव ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर, यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचाया, जहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखकर उस कन्या को लेकर मथुरा लौटे। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी दुर्गा का रूप थी और उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका काल जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद और यशोदा ने कृष्ण का बड़े प्यार से पालन-पोषण किया और कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएँ (राक्षसों का वध, गोवर्धन लीला, रासलीला) कीं। उन्होंने कहा बड़े होने पर कृष्ण मथुरा लौटे, कंस का वध किया और मथुरा की जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, जिससे धर्म की स्थापना हुई। स्वामी पद्मनारायणाचार्य महाराज जी ने श्रद्धालुओं से कहा कि यह कथा सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है और भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इससे पूर्व कथा के यजमान अमित गंभीर के परिवार द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा सुनाए गए भजनों को सुनकर श्रद्धालु झूमते रहे। इस दौरान विधायक तिलकराज बेहड़, बीना बेहड़,अध्यक्ष महेश बब्बर, महामंत्री ओमप्रकाश अरोरा, विजय जग्गा, विजय विरमानी, रोहिताश बत्रा, नन्दलाल भुड्डी, अमित अरोरा बॉबी, राकेश राजदेव, सान्या गंभीर, पूजा आशु गंभीर, मीनू दीपक गंभीर, रेखा राजीव गंभीर, वन्दना राकेश गंभीर, डिम्पल मोहित गंभीर, महक सचिन गंभीर, प्रिया रोहित गंभीर, श्रेया गंभीर, ऋषभ गंभीर, मुदित गंभीर, बंटी ग्रोवर, नरेश शर्मा, तिलक घई, सुरेश बब्बर, रमेश मिड्ढा, शशि अरोरा, राज वर्मा, पिंकी ग्रोवर, सीमा जुनेजा, किरन जग्गा, अश्विनी जुनेजा, राकेश सुखीजा, संदीप धीर, राजेन्द्र खनीजो, दीपक गुगलानी, सचिन मुजाल, पवन गाबा, यमन बब्बर, संजय जुनेजा, कृष्ण लाल नारंग, अशोक भल्ला, सुदेश मिढ्ढा, अश्वनी बजाज, मनोज मुंजाल, विशाल भुड्डी, गौरव बेहड़, राजकुमार खनीजो, अशोक भल्ला, सुरेश जग्गा, रोहित जग्गा, आकांक्षा अनेजा, बीना बत्रा, सीमा जुनेजा, मंजू राजदेव, मनोरमा देवल, स्नेहा मिढ्ढा, अंजलि ठक्कर, वर्षा अरोरा, बबीता गुप्ता आदि श्रद्धालु मौजूद थे।

SAHAS Homeo
साहस होम्यो मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक
जर्मन तथा सभी प्रकार के होम्योपैथिक व बायोकैमिक दवाईयों के विक्रेता

डॉ. यश पाण्डेय
होम्योपैथिक फिजिशियन
बी.एच.एम.एस., जयपुर
चर्म रोग | गुर्दा रोग | पेट रोग
गुदा रोग | लिवर सम्बन्धि रोग
अन्य रोग • स्पान्डीलाईटिस • श्वास रोग • मोटापा • दमा • प्रोस्टेट • माइग्रेन • टान्सिल • एलर्जी • ब्रोनकाइटिस
बच्चों के रोग • पेट का दर्द • अपच • कान में संक्रमण / दर्द • खांसी • जुकाम • निमोनिया • बुखार • दांत निकलना
साहस होम्यो क्लीनिक
निकट गुरुद्वारा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी
मो. 9456727473, 9410514531 शनिवार अवकाश

साइक्लिंग वेलोड्रम का एक वर्ष पूरा होने पर निकली साइकिल रैली

खेल सचिव अमित सिन्हा ने रैली में साइकिल चलाकर बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

रूद्रपुर। मनोज सरकार स्टेडियम में स्थित साइक्लिंग वेलोड्रम के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं साइकिल चलाकर रैली में भाग लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में भारतीय साइक्लिंग फेडरेशन के सचिव मनिंदरपाल सिंह, प्रभारी उपनिदेशक खेल श्रीमती राशिका सिद्दीकी, जिला क्रीड़ाधिकारी ऊधमसिंहनगर श्रीमती जानकी कार्की, जिला क्रीड़ा अधिकारी नैनीताल श्रीमती निर्मला पंत, उत्तराखंड आयुष परिषद के अध्यक्ष एवं चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के एमडी डॉ. केसी चंदौला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अमित सिन्हा ने अपने संबोधन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास का भी सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। अमित सिन्हा ने कहा कि एक वर्ष पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो आज पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय ट्रैक पर साइक्लिंग चौंपियनशिप में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि एशियन गेम्स के बाद दूसरी बार इस वेलोड्रम में राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन हो रहा है, जो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि हल्द्वानी से मुनस्यारी तक पूर्व में होने वाली साइक्लिंग गतिविधियों को पुनः शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी साइक्लिंग को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव मनिंदरपाल सिंह ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की पहली साइक्लिंग एकेडमी रूद्रपुर में खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश में साइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और खेल विभाग की ओर से उन्हें इसका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही प्रदेश सरकार के सहयोग से रूद्रपुर में नेशनल साइक्लिंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी, जहां 50 प्रतिशत अवसर उत्तराखंड के खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, जबकि देशभर के खिलाड़ी भी यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉ. केसी चंदौला ने कहा कि साइक्लिंग जैसे खेल युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करते हैं और नशे से दूर रखने में सहायक होते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में उत्तराखंड साइक्लिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल चौधरी, सचिव दिवेश पांडे, ओलंपिक एसोसिएशन उत्तराखंड के महासचिव डी.के. सिंह, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व खेल अधिकारी नागेंद्र शर्मा, युवा कल्याण अधिकारी भूपेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या मेंखिलाड़ी, प्रशिक्षक और खेल प्रेमी मौजूद रहे।

मोदी सरकार ने गरीबों से काम का अधिकार छीना : आलोक शर्मा

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। केंद्र की भाजपा सरकार ने वीबी जी राम जी विधेयक पास करवाकर मनरेगा व महात्मा गांधी जी की सोच की हत्या की है। मोदी सरकार ने गरीबो से काम का अधिकार छीन लिया है। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता इक दौरान कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ष्सुधारष के नाम पर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जान-बूझकर की गई कोशिश है। उन्होंने कहा मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज, काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है बल्कि 12 करोड़ एन मजदूरों के अधिकारों को भी बेरहमी से कुचला है। दो दशकों से, एनआरईजीए करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है और कोविड 19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरुरी साबित हुआ है।2014 से पीएम मोदी मनरेगा के बहुत खिलाफ रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की नाकामी की जीती-जागती निशानी कहा था। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले 11 सालों में, मोदी सरकार ने एमएनआरईजीएस को सिस्टमेटिक तरीके से कमजोर किया है और उसमें तोड़फोड़ की है। बजट में कटौती करने से लेकर राज्यों से कानूनी तौर पर जरूरी फंड रोकने, जॉब कार्ड हटाने और आधार बेस्ड पेमेंट की मजबूरी के जरिए लगभग सात करोड़ मजदूरों को बाहर करने तक। इस जानबूझकर किए गए दबाव के नतीजे में, पिछले पाँच सालों में मनरेगाहर साल मुश्किल से 50-55 दिन काम देने तक सिमट गया है। उन्होंने कहा यह सोचा-समझा खत्म करना सत्ता के नशे में चूर एक तानाशाही सरकार की सोची-समझी बदले की कार्रवाई की। यह कोई सुधार नहीं है यह गाँव के गरीबों के लिए एक संवैधानिक वादे को वापस लेना है। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने डीसेंट्रलाइजेशन को भी कुचल दिया है।सबसे खतरनाक बात यह है कि मनरेगा के डिमांड ड्रिवन नेचर को खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह एक सीमित, केंद्र द्वारा तय एलोकेशन सिस्टम लाया जा रहा है। इससे केंद्र एकतरफा फंड सीमित कर सकता है, जबकि राज्यों को किसी भी अतिरिक्त रोजगार के लिए सख्ती से केंद्र की शर्तों पर पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह रोजगार के कानूनी अधिकार को एक बजट- सीमित, अपनी मर्जी की स्कीम में बदल देता है और उन राज्यों को सजा देता है जो भूख और बेरोजगारी पर ध्यान देते हैं।यह कदम महात्मा गांधी के आदर्शों का सीधा अपमान है और ग्रामीण रोजगार पर खुली जंग का ऐलान है। रिकॉर्ड बेरोजगारी से भारत के युवाओं को तबाह करने के बाद, मोदी सरकार अब गरीब ग्रामीण परिवारों की बची हुई आखिरी आर्थिक सुरक्षा को निशाना बना रही है। हम सड़क से लेकर संसद तक, हर मंच पर इस जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी और फेडरल-विरोधी हमले का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा बारह साल बाद, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए मोदी सरकार का नेशनल हेराल्ड केस का हौवा बेइज्जती में खत्म हुआ। मोदी-शाह के झूठ कमजोर हो गए, सच जीत गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। प्रेस वार्ता में विधायक सुमित हृदयेश, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती खष्टी बिष्ट, हरीश मेहता, हेमन्त बगड़वाल, नरेश अग्रवाल, मलय बिष्ट, गोविंद बगड़वाल, संजय किरौला, महेश कांडपाल, हेमन्त पाठक आदि उपस्थित रहे।

अटल जी का जीवन राष्ट्रहित और सिद्धांतों की मिसाल: नैनवाल

अटल स्मृति वर्ष व वीर बाल दिवस पर भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

रुद्रपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला उधम सिंह नगर (रुद्रपुर) द्वारा अटल स्मृति वर्ष एवं वीर बाल दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, उनके आदर्शों एवं राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान के साथ-साथ वीर बाल शहीद साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को स्मरण किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जिला प्रभारी राकेश नैनवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि अटल जी ने सत्ता को कभी साध्य नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम माना। उनका समावेशी नेतृत्व, संवाद की राजनीति और सशक्त भारत का स्वप्न आज भी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शक है। राकेश नैनवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अटल जी के विचारों को जन-जन तक पहुँचाकर संगठन को और अधिक मजबूत करें। कार्यक्रम में सह-प्रभारी साकेत अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने विश्व मंच पर एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में पहचान बनाई। पोखरण परमाणु परीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और आधारभूत ढांचे का विस्तार उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को अटल जी के विचारों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि अटल स्मृति वर्ष और वीर बाल दिवस जैसे आयोजन केवल स्मरण तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि इनके माध्यम से हमें संगठनात्मक मजबूती और वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अटल जी के राष्ट्रवादी विचारों और साहिबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति में शुचिता, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस पर साहिबजादों का स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए आयु नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने वीर बाल दिवस के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों, विशेष रूप से छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के अद्भुत साहस, धर्मनिष्ठा और अल्प आयु में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि साहिबजादों ने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने के बजाय सत्य और धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर कर मानवता को अमर संदेश दिया। बैठक के दौरान नव-निर्मित मोर्चों के जिलाध्यक्षों का पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं माल्यार्पण के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और वैचारिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और शहीद साहिबजादों के बलिदान को घर-घर तक पहुँचाएं। कार्यक्रम में जिला महामंत्री तरुण दत्ता, जिला मंत्री अजय जोशी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता, जिला उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा, इंद्रपाल मान, हिमांशु शुक्ला, शालिनी बोरा, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा नत्रपाल मौर्य, जिला मंत्री प्रमोद मित्तल, अक्षय अरोड़ा, मीडिया संयोजक विजय तोमर, कार्यालय मंत्री मोर सिंह, सह-कार्यालय मंत्री सुरेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विपिन गहलौत, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विनीता सक्सेना, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश बजाज, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष रवि रस्तोगी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश कोली, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष पुष्केंद्र राणा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष हारून मलिक सहित सभी मंडल अध्यक्ष,मंडल महामंत्री एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कलेक्ट्रेट में शहीद ऊधम सिंह की कांस्य प्रतिमा स्थापित

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के सम्मान में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद ऊधम सिंह स्थल पर उनकी 9 फीट ऊंची कास्य प्रतिमा स्थापित की गई। यह स्थापना रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा की मौजूदगी में संपन्न हुई। विधायक के प्रयासों से स्मारक स्थल का सौंदर्यीकरण कार्य भी अंतिम चरण में है। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा शहीद ऊधम सिंह स्थल का लगभग 14 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं 22 लाख रुपये की लागत से निर्मित 9 फीट ऊंची कास्य प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसे आज स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण पूर्ण होते ही शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा का अनावरण एक भव्य एवं बड़े कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। विधायक ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह जैसे महान वीर सपूत, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष भारतीयों की शहादत का बदला लेकर देश का मान बढ़ाया, करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे महापुरुषों के स्मारक स्थल भव्य, दिव्य और आकर्षक स्वरूप में विकसित हों, यही उनका उद्देश्य है। उन्होंने विश्वास जताया कि शीघ्र ही शहीद ऊधम सिंह स्थल नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अनुभव चौधरी, समाजसेवी हरविंदर चावला, पार्षद जॉनी भाटिया, राजकुमार कोली, चन्द्रसेन चंदा, मोहित बत्रा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

दुकान पर बैठे युवक पर कृपाण से हमला,केस दर्ज

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। कोतवाली रुद्रपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।तहरीर के अनुसार इंदिरा कॉलोनी रामलीला मैदान के पास स्थित एक दुकान पर 20 दिसंबर की शाम करीब 4:30 बजे उस समय घटना हुई, जब दुकानदार का छोटा बेटा आर्यन सिंह दुकान पर बैठा था। आरोप है कि इसी दौरान हैरी खैरा अपने दो अन्य साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और आर्यन सिंह के साथ गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने आर्यन सिंह के सिर पर कृपाण से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया।घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। तहरीर में इस पूरे घटनाक्रम में हर्षद्वीप की भूमिका होने की भी बात कही गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली रुद्रपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फरार दोषसिद्ध बंदी को किया गिरफ्तार

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस ने एक मामले में न्यायालय से दोषसिद्ध बंदी को पैरोल पर रिहा होने के बाद समय अवधि पूरी होने के बाद भी न्यायालय में समर्पण न करने पर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविद-19 के दौरान पैरोल में रिहा सिद्ध दोष बंदी अंतरिम से जमानत पर रिहा बंदियो को तस्दीक कर गिरफ्तारी एवं आत्म समर्पण की कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रम में ट्रांजिट कैम्प कोतवाली पुलिस द्वारा सिद्ध दोष बंदी राहुल राय पुत्र विष्णु राय निवासी तीनपानी, ट्रांजिट कैंप को गिरफ्तार कर उप कारागार हल्द्वानी में दाखिल किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में अपर उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश बावड़ी व हेड कॉस्टेबल अनिल कुमार शामिल थे।

इंडियन डेंटल एसो. की नई कार्यकारिणी का गठन

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) उधम सिंह नगर की एक महत्वपूर्ण बैठक सोनिया होटल, रुद्रपुर में आयोजित की गई। बैठक में किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, हल्द्वानी एवं बिलासपुर से आए सम्मानित दंत चिकित्सकों ने सहभागिता की।बैठक की अध्यक्षता डॉ. अशोक प्रकाश अग्रवाल ने की। इस अवसर पर वर्ष 2026 के लिए इंडियन डेंटल एसोसिएशन उधम सिंह नगर की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। इसमें डॉ. महेंद्र सिंह को अध्यक्ष, डॉ. मनी खुराना को सचिव तथा डॉ. शिवम रस्तोगी को कोषाध्यक्ष चुना गया।बैठक में दंत चिकित्सकों ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, पेशेवर हितों की रक्षा तथा जनमानस में दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।इस अवसर पर डॉ. दीपिका जैन, डॉ. मन्नू सिंह, डॉ. प्रियंका गर्ग, डॉ. मानसी बंसल, डॉ. अभिलाषा टंडन, डॉ. मलखान सिंह, डॉ. विक्रम आनंद, डॉ. क्षितिज छाबड़ा, डॉ. अंकित गर्ग, डॉ. तुषार मित्तल, डॉ. लव शर्मा, डॉ. कोमल सिंह चीमा, डॉ. अनुराग अग्रवाल, डॉ. पीयूष टंडन एवं डॉ. शुभम संदेश जैन सहित अनेक दंत चिकित्सक उपस्थित रहे।

आर.ए.एन. किड्स स्कूल में एनुअल बोनांजा की धूम

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। आरएएन किड्स स्कूल के प्रांगण में कक्षा - एल केजी और यूकेजी का एनुअल बोनांजा 'द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस' बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन विंग कमांडर एच. के. राय, प्रबंधक मोहित राय एवं एडवाइजर श्रीमती रेखा कर्नाटक द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की हैड मिस्ट्रेस श्रीमती गरिमा घई ने सभी अतिथियों व माता-पिता का स्वागत किया। कक्षा एफ-2 एवं एफ-3 के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने वेलकम डांस, योगा, स्किट- मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैप्पीनेस इन स्कूल, डांस ऑफ सेंस ओर्गंस, मेगा इवेंट ख्र हमारे नेशनल सिम्बल्स, जिंगल बैल्स प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय प्रबंधक मोहित राय ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की एडवाइजर रेखा कर्नाटक ने इस उपलक्ष पर अपने विचार प्रकट किए। समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रयास को बहुत सराहा।

उत्तरांचल दर्पण
सम्पादकीय
सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

एसआईआर से कटते नाम

बिहार की तर्ज पर अब अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के नाम इस सूची से हटाए जाने की आशंका है। चुनाव आयोग की ओर से हाल में जारी मसौदा सूची में तमिलनाडु में 97.40 लाख और गुजरात में 73.73 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें समय पर आवश्यक दस्तावेज दर्ज न कराना भी शामिल है। अंतिम सूची जारी होने से पहले ऐसे लोगों को अपनी आपत्तियां और दावे पेश करने का मौका दिया जाएगा और संभव है कि कई मतदाताओं के नाम फिर से जुड़ जाएंगे। मसौदा सूची के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो उससे यही लगता है कि नाम दर्ज कराने के आखिरी अवसर के बाद भी बड़ी संख्या में लोग इस सूची से बाहर रह जाएंगे। सवाल है कि अगर इन लोगों के पास मतदान की पात्रता नही है, तो पहले इनका नाम क्यों और कैसे मतदाता सूची में था? बिहार में एसआइआर की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले पहचान पत्र के मसले पर विवाद पैदा हुआ था। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को नागरिकता का पहचान पत्र मानने से इनकार दिया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आधार को पहचान पत्र के दस्तावेजों में शामिल किया गया। बिहार में भी मसौदा सूची में करीब पैंसठ लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। हालांकि बाद में उसमें कई नाम जोड़े गए, इसके बावजूद अंतिम सूची में करीब सैंतालीस लाख लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए। शीर्ष अदालत ने इस पर सूची से हटाए गए लोगों का कारण सहित विस्तृत ब्योरा मांगा। यही स्थिति अब अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। इस सबके बीच विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को भी कसौटी पर कसा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो मसविदा सूची से हटाए गए लोगों का सत्तारूढ़ दल ने अपने स्तर पर सत्यापन करने की मुहिम शुरू कर दी है। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर चुनाव आयोग पर आम लोगों और राजनीतिक दलों का भरोसा क्यों डगमगाने लगा है? इसमें दोराय नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में समय-समय पर संशोधन कर अपात्र लोगों या मृतकों के नाम हटाए जाने जरूरी है। मगर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पैमाना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि न तो किसी के मन में कोई आशंका रहे और न ही कहीं से कोई सवाल उठने की गुंजाइश बचे। यह चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी को कोई आशंका हो, तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। ऐसा न होने पर आयोग की विश्वसनीयता पर अंगुली उठना स्वाभाविक है।

जरूरी है बांधों की तत्काल मरम्मत

देश में बड़े बांधों की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। संसद के चालू सत्र में जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि देशभर में 216 बांध ऐसे हैं, जिनमें गंभीर खामियां पाई गई हैं और जिनकी तत्काल मरम्मत होना जरूरी है। इन बांधों को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि बांध में बड़ी संरचनात्मक या तकनीकी कमी है, जिसे नजरअंदाज करना भविष्य में बड़े खतरे को आमंत्रण देना होगा ? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 50 ऐसे बांध पाए गए हैं, जिनकी तत्काल मरम्मत जरूरी है। इसके बाद मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 24-24 बांध, तमिलनाडू में 19, तेलंगाना में 18, उत्तरप्रदेश में 12, झारखंड में 10, केरल में 9, आंध्रप्रदेश में 7 और गुजरात तथा मेघालय में छह-छह बांध क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिनमें तत्काल सुधार जरूरी है। यह समझ से परे है कि 'बांध सुरक्षा विधयक' अस्तित्व में होने के बावजूद इन बांधों की मरम्मत पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया।नदियों पर बांध इस दृष्टि से बनाए गए थे, जिससे जल के इन अक्षुण भंडारों से सिंचाई, बिजली और महानगरों के लिए पेयजल की आपूर्ति के साथ पानी की बर्बादी पर अंकुश लगे। लेकिन औसत आयु पूरी होने से पहले ही देश के ज्यादातर बांध एक तो गाद से भर गए, दूसरे बांधों की पक्की दीवारों में क्षरण होने से पानी का रिसाव बढ़ गया। पुराने होने से कई बांध बरसात में ज्यादा पानी भर जाने पर टूटने भी लगे हैं। बांधों में की गाद भर जाने से जलग्रहण क्षमता कम हुई है। नतीजतन ये जल्दी भर जाते हैं।ऐसे में बांधों से छोड़ा गया पानी तबाही का कारण बन रहा है। इस नाते बांधों की मरम्मत के लिए, समय रहते भारत सरकार ने देशभर के बांधों को सुरक्षित बनाए रखने की दृष्टि से 10,211 करोड़ रुपए का बजट भी आबंटित किया हुआ है। यह धन बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी) के अंतर्गत दिया है। इस राशि से दो चरणों में बांधों की मरम्मत करने के प्रावधान हैं। भारत बांध संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। देश में कुल बांध 5,745 हैं। इनमें से संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने 1115 बांधों की हालत खस्ता बताई है। चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। देश में 973 बांधों की उम्र 50 से 100 वर्ष के बीच है, जो 18 प्रतिशत बैठती है। 973 यानी 56 फीसदी ऐसे बांध हैं, जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष हैं। शेष 26 प्रतिशत बांध 25 वर्ष से कम आयु के हैं, जिन्हें मरम्मत की अतिरिक्त जरूरत नहीं है। दरअसल पुराने और ज्यादा जल दबाव वाले बांधों की मरम्मत इसलिए जरूरी है, क्योंकि अधिक मात्रा में बरसाती पानी भर जाने पर इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बांधों की उम्र पूरी होने पर रख-रखाव का तो खर्च बढ़ता है, लेकिन जल भंडारण क्षमता घटती है। बांध बनते समय उनके आसपास आबादी नहीं होती है, लेकिन बाद में बढ़ती जाती है। नदियों के जल बहाव के किनारों पर आबाद गांव, कस्बे एवं नगर होते हैं, ऐसे में अचानक बांध टूटता है तो लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। भारत में बांधों की मरम्मत अप्रैल 2021 से लेकर 2031 तक पूरी होनी है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक-2018 पारित कर दिए जाने के बाद से ही यह उम्मीद थी कि जिन बांधों की उम्र 26 से 100 वर्ष की है उनकी कालांतर में मरम्मत की जाएगी। कई बांध इतनी जर्जर अवस्था में आ गए हैं कि बांध की दीवारों, मोरियों और द्वारों से निरंतर पानी रिसता रहता है। इस नजरिए से इस विधेयक का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और संस्थागत कार्ययोजना उपलब्ध कराना है। भारत में बांधों की सुरक्षा के लिए कानून की कमी के कारण यह चिंता का मुद्दा था। खासतौर से बड़े बांधों का निर्माण देश में बड़ी बहस और विवाद के मुद्दे बने हैं। फरक्का, नर्मदा सागर और टिहरी बांध के विस्थापितों का आज भी सेवा-शर्तों के अनुसार उचित विस्थापन संभव नहीं हुआ है। बड़े बांधों को बाढ़, भू-जल भराव क्षेत्रों को हानि और नदियों की अविरलता के लिए भी दोषी माना गया है। 1979 में गुजरात के मोरवी बांध के टूटने से पांच हजार और 11 अगस्त 1979 को गुजरात की मच्छू नदी पर बने बांध के टूटने से 2000 लोगों की मौतें हुईं थीं। 2010 में भारत, नेपाल सीमा पर कोसी नदी का बांध टूटने से सैंकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे।भारत के हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नदियों और पहाड़ों के होने से अनेक बांधों का निर्माण संभव हुआ है। यहां 5,745 से भी ज्यादा बड़े बांध हैं। 450 बड़े बांध निर्माणाधीन भी हैं। इसके अलावा हजारों मध्यम और लघु बांध हैं। भारतीय भौगोलिक परिस्थिति व अनुकूल जलवायु का ही कमाल है, जो इतने छोटे-बड़े बांधों का निर्माण संभव हुआ। भारत में बांधों का निर्माण आजादी के पूर्व से ही आरंभ हो गया था, इसलिए 164 बांध सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 75 प्रतिशत बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बांधों का समुचित रख-रखाव नहीं होने के कारण 36 बांध पिछले कुछ दशकों के भीतर टूटे भी हैं। इनके अचानक टूटने से न केवल पर्यावरणीय क्षति हुई, बल्कि हजारों लोगों की मौतें भी हुईं। इस कानून के मुताबिक, प्रत्येक राज्य में स्थित बांधों की सुरक्षा के लिए एनडीएसए स्थापित किया जाएगा। एक राज्य के स्वामित्व वाले बांध, जो किसी अन्य राज्य में या केंद्रीय लोक सेवा उपक्रमों (सीपीएसयू) के अंतर्गत आने वाले बांध या वे बांध जो दो या दो से अधिक राज्यों में फैले हैं, सभी एनडीएसए के अधिकार क्षेत्र में होंगे। इसी कारण तमिलनाडु जैसे राज्यों की ओर से विधेयक का विरोध किया गया था। क्योंकि यह राज्य केरल में कई बांधों का प्रबंधन करता है। मुल्ला पेरियार बांध इनमें से एक है। विरोधी राज्यों को शंका थी कि यह विधेयक उनकी शक्ति कमजोर करेगा। 2014 में तमिलनाडु एवं केरल सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे। तमिलनाडु अपने यहां बांधों की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि करना चाहता था, जबकि केरल ने सुरक्षा का हवाला देते हुए विरोध किया था। अब जो बांध दो या दो से अधिक राज्यों की आर्थिक मदद से निर्माणाधीन होने के कारण विवादग्रस्त हैं, उनके समाधान का रास्ता भी खुल गया है। भविष्य में यदि नदी जोड़ो अभियान जोर पकड़ता है तो बांध और नहरों के निर्माण से लेकर दो या इससे अधिक राज्यों में जल-बंटवारे को लेकर जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें निपटाने में सुगमता होगी।

प्रमोद भार्गव,लेखक/पत्रकार

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला और वैश्विक चुप्पी

दो दिन पहले तक दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का उपदेश दिया जा रहा था। बड़े मंचों से भाषण हो रहे थे, मानवता और सभ्यता की दुहाई दी जा रही थी। लेकिन आज वही दुनिया बांग्लादेश में बहते हिंदुओं के खून पर खामोश है। वही ताकतें, जो खुद को मानवाधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक बताती हैं, आज ऐसी चुप्पी साधे बैठी हैं मानो कुछ हुआ ही न हो। बांग्लादेश में जो कुछ बीते दिनों हुआ, वह सिर्फ एक पड़ोसी देश की आंतरिक अशांति नहीं है, बल्कि यह उस सलेक्टिव सोच और वैचारिक पाखंड का आईना है, जिसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए। बांग्लादेश में हालात उस वक्त बिगड़ने शुरू हुए, जब कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद सड़कों पर उन्मादी भीड़ उतर आई। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और अराजकता फैल गई। मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया, सरकारी संपत्ति जलाई गई और भारत विरोधी नारे खुलेआम लगाए गए। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से पनप रही कट्टर सोच का विस्फोट था।इस उन्माद की सबसे भयावह तस्वीर मैमनसिंह जिले से सामने आई। यहां एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने घेर लिया। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। यहीं तक भी दरिंदगी नहीं रुकी। युवक के शव को पेड़ से लटकाया गया और बीच सड़क पर लाकर आग लगा दी गई। यह घटना किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि यह साफ संदेश था कि कट्टरपंथी भीड़ कानून, संविधान और इंसानियत से ऊपर खुद को मानने लगी है।इस बर्बरता के बाद सवाल उठना स्वाभाविक था कि दुनिया क्या बोलेगी। लेकिन यहां भी वही पुरानी कहानी दोहराई गई। पश्चिमी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। न कोई तीखा बयान, न कोई सख्त चेतावनी। मानो एक हिंदू की हत्या कोई मायने ही नहीं रखती। इसके उलट जब ढाका में अखबारों के दफ्तर जले, तब प्रेस स्वतंत्रता की चिंता में बयान जारी होने लगे। यह फर्क साफ बताता है कि मानवाधिकारों की परिभाषा किसके लिए है और किसके लिए नहीं।ढाका में प्रथम आलो और द डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के दफ्तरों पर हमला हुआ। आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पश्चिमी देशों के मीडिया संगठनों ने प्रेस नोट जारी कर चिंता जताई। यह चिंता अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि उसी ढाका से कुछ ही दूरी पर जब एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया, तब इनकी जुबान क्यों बंद हो गई। क्या इंसान की जान से ज्यादा इमारतें कीमती हैं।बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जरूर इस हत्या की निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर डर का माहौल कायम है। हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़ और जबरन पलायन की खबरें आती रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हिंसा ने बेहद क्रूर रूप ले लिया। इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक और तस्वीर सामने आई, जिसने भारत में आक्रोश को और बढ़ा दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शरीफ उस्मान हादी को श्रद्धांजलि दी। वही हादी, जिसकी पहचान भारत विरोधी राजनीति से जुड़ी रही है। वही हादी, जिसका नाम ग्रेटर बांग्लादेश जैसे विवादित नक्शे से जुड़ा, जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। सवाल यह है कि जब बांग्लादेश की संस्थाएं खुलेआम भारत विरोधी सोच को सम्मान दे रही हैं, तो भारत को भी आंख बंद कर रिश्ते निभाने चाहिए या नहीं।यही सवाल अब भारतीय क्रिकेट और आईपीएल तक पहुंच गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को करोड़ों रुपये में खरीदे जाने पर बहस तेज हो गई है। खेल भावना की दुहाई देने वाले कह रहे हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन जब खेल संस्थाएं ही राजनीतिक संदेश देने लगें, तब यह तर्क कमजोर पड़ जाता है। अतीत में मुस्तफिजुर के भारत विरोधी पोस्ट लाइक करने को लेकर विवाद हो चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत अपने ही खिलाफ जहर उगलने वालों पर पैसा और सम्मान लुटाए।सोशल मीडिया पर आज यही बहस छाई हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है और भारत विरोधी सोच को महिमामंडित किया जा रहा है, तो बीसीसीआई और आईपीएल क्यों चुप हैं। क्या भारत प्रथम का विचार सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा या फैसलों में भी दिखेगा।यह मुद्दा सिर्फ क्रिकेट या एक खिलाड़ी का नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। पाकिस्तान के मामले में भारत ने साफ रुख अपनाया। खेल संबंध तोड़े गए, संदेश साफ दिया गया। अब जब बांग्लादेश में भी वही पाकिस्तान जैसी सोच उभरती दिख रही है, तो क्या भारत को अलग मापदंड अपनाने चाहिए। बांग्लादेश की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, वह पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी है। कट्टरपंथ किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं रहता। यह जहां भी पनपता है, वहां इंसानियत को कुचल देता है। आज निशाने पर हिंदू हैं, कल कोई और हो सकता है। यही कारण है कि इस वैचारिक आतंक के खिलाफ स्पष्ट और बिना दोहरे मापदंड के लड़ाई जरूरी है।दुनिया को यह समझना होगा कि इस्लामिक कट्टरपंथ सिर्फ यहूदियों या पश्चिमी देशों के लिए खतरा नहीं है। यह उतना ही बड़ा खतरा हिंदुओं और एशिया के देशों के लिए भी है। एक हिंदू की हत्या भी उतनी ही मानवता विरोधी है, जितनी किसी और की। जब तक यह बात स्वीकार नहीं की जाएगी, तब तक मानवाधिकार की बातें खोखली रहेंगी। भारत के सामने आज भावनाओं से नहीं, बल्कि सख्त नीति से काम लेने का वक्त है। दोस्ती उन्हीं से हो सकती है, जो दोस्ती की कद्र करें। जो भारत के खिलाफ सोचेंगे, भारत विरोधी उन्माद को बढ़ावा देंगे, उन्हें यह संदेश साफ मिलना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यही समय की मांग है और यही भारत के हित में है।

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

देवभूमि उत्तराखंड तक पहुंचा प्रदूषण का जहर

उत्तर भारत इस वक्त एक मूक आपदा से जूझ रहा है। सांस लेना अब स्वाभाविक क्रिया नहीं, बल्कि जोखिम भरा काम बन चुका है। दिसंबर 2025 की ठंड के साथ वायु प्रदूषण ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की घाटियों तक हवा जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 'गंभीर' श्रेणी को पार कर 'खतरनाक' स्थिति में दर्ज किया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीधे तौर पर हेल्थ इमरजेंसी मान रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई लगातार 450 से 600 के बीच बना हुआ है। आनंद विहार, मुंडका जैसे क्षेत्रों में हालात सबसे खराब हैं, जहां स्मॉग की मोटी परत ने दिन में भी रात जैसा अंधेरा पैदा कर दिया है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां एक्यूआई 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया है। ठंडी हवा, कम दृश्यता और जहरीले कणों ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रदूषण अब केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड, जिसे अब तक स्वच्छ हवा का भरोसेमंद ठिकाना माना जाता था, वहां भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। देहरादून में ϧ250 से 350 के बीच पहुंच चुका है। दून घाटी की भौगोलिक संरचना के कारण प्रदूषित हवा बाहर नहीं निकल पा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों और दिल्लीख्रदेहरादून एक्सप्रेसवे से उड़ती धूल ने शहर की फिजा को जहरीला बना दिया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी स्थिति गंभीर है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और घना कोहरा मिलकर खतरनाक स्मॉग बना रहे हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद पीएम 2.5 के सूक्ष्म कण फेफड़ों के जरिए सीधे रक्त में प्रवेश कर रहे हैं। इससे अस्थमा और सांस के मरीजों की हालत बिगड़ रही है, वहीं स्वस्थ लोगों में भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक खतरनाक मानी जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण का सबसे सख्त चरण लागू कर दिया है। इसके तहत ट्रकों की एंट्री पर रोक, निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने और दफ्तरों को सीमित क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती और धूल नियंत्रण के उपाय लागू किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की कम गति और गिरते तापमान ने प्रदूषकों को वातावरण में फंसा दिया है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें, सुबह की सैर से बचें और बाहर जाते समय छ95 मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। उत्तर भारत फिलहाल सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजर रहा है और यह संकट चेतावनी दे रहा है कि अगर अब भी नहीं चेते, तो इसकी कीमत सांसों से चुकानी पड़ेगी।

-प्रदीप फुटेला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दायित्व ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

वर्ष 2025 चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए उपलब्धियों का वर्ष

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और आधुनिक चिकित्सा सेवाएँ एक साथ हो रही विकसित

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के सतत मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड का चिकित्सा शिक्षा विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों और साथ ही युवाओं को उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें ।वर्ष 2025 चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है। मानव संसाधन की कमी को दूर करने, मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों को सशक्त बनाने, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार करने और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपनाने की दिशा में विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। ये प्रयास न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस वर्ष राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 07 स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति की गई। संकाय सदस्यों की कमी को दूर करने के लिए 18 प्रोफेसर और 36 एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही 439 असिस्टेंट प्रोफेसर के सापेक्ष 142 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन पूर्ण किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली नर्सिंग सेवाओं को मजबूती देने हेतु भी सरकार ने बड़े कदम उठाए। वर्ष 2025 में 1248 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 14 सीएसएसडी/ओटी टेक्नीशियन और 73 फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में वर्ष 2025 में मानव संसाधन और शैक्षणिक ढांचे दोनों को मजबूत किया गया। एक प्रोफेसर, छह एसोसिएट प्रोफेसर और 26 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति पूरी की गई। इसके साथ ही विभाग ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए पदों का सृजन किया, जिनमें उप प्राचार्य, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर शामिल हैं। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी नर्सिंग कॉलेजों में एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत से राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त नर्सिंग पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा।वर्ष 2025 में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में 750 सीटों और राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में 1000 सीटों की क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। दून चिकित्सालय में 04 नए इमरजेंसी

ऑपरेशन थिएटर शुरू किए गए, जिससे आपातकालीन सर्जरी सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित किए गए हैं। इन विभागों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए वेतनमान में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है प्रोफेसर को 5 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर को 3 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 लाख प्रतिमाह प्रदान किए जाने का निर्णय हुआ। संविदा पर कार्यरत फैकल्टी के वेतन में भी वृद्धि की गई है, जिससे अनुभवी चिकित्सकों की राज्य में निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पीजी सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 में कुल 68 पीजी सीटों की वृद्धि हुई है। इनमें अल्मोड़ा में 35, हल्द्वानी में 13, देहरादून में 10 और श्रीनगर में 10 सीटें शामिल हैं ।राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत आई बैंक और कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र की शुरुआत कर दी गई है। इससे नेत्र प्रत्यारोपण के लिए मरीजों को अब राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं, दून चिकित्सालय में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की सुविधा शुरू की गई है, जो गंभीर रोगों के उपचार में अत्यंत उपयोगी मानी जाती है।राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में 150 शैया का पृथक चिकित्सालय तैयार किया गया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पुरुष छात्रावास और 60 फैकल्टी के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य के पहले कैंसर संस्थान, हल्द्वानी का निर्माण लगभग 41 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों का निर्माण क्रमशः 40 और 51 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। दून मेडिकल कॉलेज परिसर में पीजी हॉस्टल, इंटर्न हॉस्टल, एसआर/आर हॉस्टल और 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।वर्ष 2026 के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ तैयार की हैं। राज्य में कुल 07 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 05 कार्यशील और 02 निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध कराना है। सुपर स्पेशियलिटी सेंटर, स्टेट कैंसर संस्थान का विस्तार, रेडियोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी जैसी सुविधाएँ राज्य को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दीर्घकालिक और समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि विभाग का लक्ष्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था तैयार करना है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और आधुनिक चिकित्सा सेवाएँ एक साथ विकसित हों। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन की कमी को दूर करना, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार करना और नई तकनीकों को अपनाना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को मिलेगा 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

देहरादून। प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। इस कड़ी में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 50 प्रतिशत भत्ता देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही चिकित्सकों की कमी को दूर करना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कई पर्वतीय जिलों में भौगोलिक विषमताओं, सीमित संसाधनों और कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण चिकित्सक तैनाती से बचते रहे हैं। परिणामस्वरूप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी हमेशा ही महसूस होती रही है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को अक्सर इलाज के लिए मैदानी इलाकों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। साथ ही इलाज में भी देरी होती है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार यहां चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत यू कोट वी पे जैसी योजना भी लागू की गई है, यद्यपि इसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता देने की योजना बनाई गई है। कहा गया है कि यह भत्ता उन्हें वहां रहने और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। यह भत्ता केवल उन्हीं चिकित्सकों को दिया जाएगा जो वास्तविक रूप से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत होंगे। साथ ही उनकी निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र भी विकसित करेगी, ताकि चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार का कहना है कि चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्ताव बनाया जा रहा है।

पेज एक का शेष...

जनता की सहयोगी...इस अवसर पर उन्होंने शिशु विद्या मंदिर के बच्चों के साथ संवाद किया, जहाँ बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपनी पढ़ाई, खेल और अन्य समस्याओं को साझा किया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा भाजपा सरकार हमेशा जनता की सहयोगी रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके लिए हम 45 दिन तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 23 विभागों की सुविधाएं एक साथ जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल से आम नागरिक अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकेंगे और शिकायतों का त्वरित निस्तारण होगा। इससे पहले सीएम धामी ने ताड़ीखेत में जोरदार रोड शो भी निकाला, जिसमें विभिन्न स्थानों पर सीएम का स्वागत करने के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास की उम्मीदों को साझा किया। इस अवसर पर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

संस्कृति संरक्षण एवं ...कर लिया गया है और विद्यालयी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा की सिफारिश के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों को अगले शिक्षा सत्र से लागू किया जाना प्रस्तावित है। वहीं राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा के राज्य समन्वयक रवि दर्शन तोपाल ने इस संबंध में बताया कि राज्य के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू है। एनईपी के तहत इसमें 20 से 30 प्रतिशत बदलाव होना है। इसी के तहत रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग भी राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल किये गये है तथा सरकार की ओर से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। लिहाजा, सरकारी और अशासकीय स्कूलों के बच्चे अब इसे कोर्स में पढ़ सकेंगे ।राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा के राज्य समन्वयक ने आगे बताया कि सीएम की घोषणा के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने हमारी विरासत और विभूतियां पुस्तक तैयार की है, जिसे कक्षा छह से आठ तक सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और अब उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे राज्य आंदोलन के इतिहास के साथ ही कारगिल के अमर शहीदों के बलिदान को भी पढ़ेंगे।

वरिष्ठ प्राध्यापिका को डिजिटल अरेस्ट कर 1.11 करोड़ की ठगी

कोटद्वार। राजकीय पीजी कॉलेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका को डिजिटल अरेस्ट कर 1.11 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल पर खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर आरोपी ने प्राध्यापिका को झांसे में लिया। इसके बाद इस कदर दहशतजदा कर दिया कि 11 दिनों में उन्होंने न सिर्फ अपनी जमापूंजी गंवाई बल्कि रिश्तेदारों से भी रकम लेकर ठगों के हवाले कर दिया।इसके बाद हिम्मत जुटा प्राध्यापिका ने कोटद्वार कोतवाली पहुंच आपबीती सुनाई। फिर कोटद्वार साइबर सेल में जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला एसटीएफ देहरादून को स्थानांतरित कर दिया गया। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापिका ने प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ के साथ कोतवाली पहुंचकर घटना के संबंध में शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अपने आवास पर अकेली रहती हैं। बीती आठ दिसंबर को उनके पास अज्ञात नंबर साइबर ठग ने व्हाट्सएप पर कॉल किया। साथ ही खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर प्राध्यापिका का नंबर संगीन मामले में शामिल होने की बात कही। प्राध्यापिका के अनुसार, बातचीत के दौरान मामला संगीन बताते हुए आरोपी ने किसी भी समय गिरफ्तारी का डर दिखाया। इसके साथ ही उन्हें कॉल कट नहीं करने और लगातार व्हाट्सएप पर संपर्क में रहने का मानसिक दबाव बनाया। फिर बचाव के लिए उनसे रुपयों की डिमांड की गई। प्राध्यापिका ने पीछा छुड़ाने के लिए अपनी समस्त जमा पूंजी बताए गए नंबर पर ट्रांसफर कर दी। इसके बाद प्राध्यापिका को फिर से डिजिटल अरेस्ट कर उनसे और रुपयों की डिमांड की गई। इस बार उन्होंने अपने संबंधियों की मदद से भी लाखों रुपये ट्रांसफर कर दिए। अलग-अलग तारीखों (8,16,18 व 19) में साइबर ठगों को 1.11 करोड़ रुपये देने के बाद प्राध्यापिका की आंख खुली।

चलती कार में लगी आग, हल्द्वानी के पांच क्रिकेटर थे सवार ,सुरक्षित

देहरादून। रिस्पना पुल में अफरा-तफरी मच गई। अचानक यहां चलती काम में आग लग गई। बता दें कि कार में पांच युवक सवार थे। सभी छिदरवाला की तरफ से आ रहे थे। बता दें कि पेशे से युवक हल्द्वानी के क्रिकेटर बताए जा रहे है। दरअसल ये मामला थाना नेहरू कॉलोनी इलाके का है। दरअसल चलती कार के बोनट से अचानक धुंआ निकलने लगा। ये देखकर पांचों युवक गाड़ी से तुरंत निकल गए। जैसे ही युवक गाड़ी से निकले गाड़ी आग का गोला बन गई।सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पाया। राहत की बात ये है कि सभी युवक सुरक्षित है । बता दें कि पांचों युवक क्रिकेटर है। जो हल्द्वानी से देहरादून टूर्नामेंट खेलने आए थे। सभी युवक छिदरवाला आयुष एकेडमी से मैच खेल कर आ रहे थे।

स्कूल में घुसा... खेत में घास लेने गई महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। थानो वन रेंज ने भालू संभावित क्षेत्रों में छह सदस्यीय वन प्रहरी टीम गठित की है। यह टीम स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने के साथ-साथ घास और लकड़ी लेने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा, संभावित क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाई गई है और भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन अधिकारियों ने लोगों से चेतावनी दी है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और जंगल में काम करने वाली महिलाओं को भालुओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

पूर्व प्रधान ने ... दी कि जब तक तहसील प्रशासन लिखित स्पष्टीकरण नहीं देगा, वे अपने समर्थकों के साथ अनिश्चित कालीन धरने पर बने रहेंगे। धरने में अशोक राणा, सतनाम सिंह करनावल, हरिओम सिंह राणा, राज सिंह सुच्चा, प्रकाश सिंह बब्बर, विजेंद्र सिंह मोमी सहित कई समर्थक मौजूद रहे।

बुलडोजर कार्रवाई...लाभ मिलने के साथ ही ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार और क्षेत्र पंचायत की बैठक में मनोनीत ग्राम प्रधान के भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो रामनगर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में वन ग्राम के ग्रामीण अपने वोटों के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय लेंगे।

बजरंग दल ने बाईक रैली निकाल मनाया शौर्य दिवस

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बजरंग दल द्वारा रविवार को शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बजरंग दल द्वारा शौर्य बाईक रैली का आयोजन किया गया। बाईक रैली लक्ष्मी शिशु मंदिर से आरंभ होकर सिंधी चौराहा, नैनीताल रोड़ , तिकोनिया होते हुए वापिस बाजार से होते हुए लक्ष्मी शिशु मंदिर में समाप्त हुई। रैली में 300 से अधिक बाईक,15 चार पहिया वाहन, एक डी.जे. वाहन, एक जे. सी.बी.,एक ट्रैक्टर और लगभग 700 लोग शामिल हुए। बजरंग दल संयोजक अंकित पाल ने बताया कि इस यात्रा को निकालने का मुख्य मकसद हिन्दू एकता को दर्शाना था और उन्होंने बताया कि हिन्दू एक है और हमेशा एक रहेगा।

यीशु भक्त सत्संग समिति द्वारा किया गया महा रैली का आयोजन

गदरपुर । यीशु भक्त सत्संग समिति के द्वारा ग्राम राम जीवनपुर नंबर 3 से क्रिसमस के पावन पर्व के उपलक्ष में एक महा रैली का आयोजन किया गया। रैली ग्राम रामजीवनपुर से मुख्य बाजार होते हुए दिनेशपुर मोड़ से वापस ग्राम राम जीवन पुर पहुंचकर संपन्न हुई । रैली में यीशु भक्ति सत्संग समिति के अध्यक्ष पास्टर सुरेंद्र सागर द्वारा प्रभु यीशु के जन्म दिवस के बारे में प्रकाश डाला गया ,वहीं उनके द्वारा कहा गया कि यीशु मसीह संपूर्ण संसार के लोगों के लिए उद्धार का मार्ग हैं । उनके द्वारा संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की गई । महारैली में अध्यक्ष सुरेंद्र सागर ,उपाध्यक्ष सरिता सागर के अलावा सदस्य अजय कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक मसीह, रेखा सिंधी, सौरभ, पूजा, नेहा, कोमल, भावना, वंदना, शिवा, अभि, सुमन आदि शामिल रहे।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा
स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

परिवर्तन संस्था भारत का द्वितीय अधिवेशन सम्पन्न

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। परिवर्तन संस्था भारत का द्वितीय अधिवेशन एक होटल में आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता वेदवीर सिंह आदिवासी जी ने की, जबकि संचालन ई. राकेश कुमार जी, जिलाध्यक्ष उधमसिंहनगर ने किया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख चौ0 विनोद अम्बेडकर जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। अधिवेशन का प्रारंभ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर और संस्था के समूह गान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि चौ0 विनोद अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त क्षेत्रवादी और जातिवादी विचारधारा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उद्देश्यहीन संगठन और व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित नेता समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस कारण समाज जातियों में बिखरा हुआ है, शिक्षा से वंचित है और शोषण एवं अन्याय झेल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि परिवर्तन संस्था के पास 30 वर्षों का कैडरबेस, अनुभव और राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा है। यह संगठन समाज के बौद्धिक स्तर और चरित्र को ऊंचा उठाकर एकजुटता स्थापित करने में सक्षम है। अम्बेडकर ने पदाधिकारियों से अपील की कि वे समाज में जाकर संवाद और संपर्क बढ़ाएं और लोगों को सही और गलत, मित्र और शत्रु की पहचान करना सिखाएं। ऐसा करने से समाज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाकर राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि परिवर्तन संस्था द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के समता, समानता और बंधुत्व के महापुरुषों के आंदोलनों को समय, मन और संसाधनों से सहयोग देना चाहिए। जिला अधिवेशन में अशोक गौतम, सरदार बोबी सिंह, रामरतन लाल, कु0 शिवांगी, वेदप्रकाश दिवाकर, हरकेश सिंह, अक्षय लाल, विशाल कुमार, मनोहर लाल, सेवाराम दिवाकर, भगीरथ, मुकेश कुमार सहित कई स्त्री और पुरुष सदस्य उपस्थित रहे।

हल्द्वानी में दिनदहाड़े युवक के साथ हजारों रूपये की लूट

हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र स्थित राम मंदिर वाली गली में युवक से दिनदहाड़े लूट हो गई। युवक हल्द्वानी बाजार में खरीदारी करने पहुंचा था। जहां एक नशेड़ी ने उससे 8800 रुपए छीन लिए।खनस्यू हरिशताल निवासी पीड़ित रमेश चन्द्र भट्ट ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर सौंपकर बताया कि 16 दिसंबर मंगलवार के दिन लगभग दोपहर के 1:30 बजे वह खरीदारी के लिए पटेल चौक से डीके पार्क की ओर जा रहा था।इस दौरान राम मंदिर वाली गली में चेहरे पर चोटों के निशान वाले एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर धमकाने लगा। आरोप है कि आरोपित ने जबरन पीड़ित की जेब में हाथ डाकर 8,800 रुपये नकद निकाल लिए और मौके से फरार हो गया।घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में फुटेज चेक की। लेकिन वहां कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। इसके बाद दो पुलिसकर्मी पीड़ित के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जहां राम मंदिर गली में लगे सीसीटीवी की जांच की गई। जांच में पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड पाया गया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पार्षद सौरभ ने की माता गुजरी नाम से द्वार बनाने की मांग

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। वार्ड 39 से कांग्रेस पार्षद सौरभराज बेहड़ ने मेयर विकास शर्मा से मुलाकात कर उनसे वार्ड में माता गुजरी के नाम से द्वार बनाने की मांग कर ज्ञापन सौंपा। श्री बेहड़ ने कहा कि उनके वार्ड क्षेत्र में बेदी सीमेंट के पास एक तिराहा स्थित है, जो स्थानीय नागरिकों में माता गुजरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान क्षेत्रवासियों की धार्मिक आस्था एवं भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मेयर से कहा आमजन की भावनाओं एवं साक्षी स्थलों को ध्यान में रखते हुए उक्त तिराहे पर एक भव्य द्वार का निर्माण कराने की कृपा करें, जिसका नाम ष्माता गुजरी द्वारष् रखा जाए। इससे न केवल क्षेत्र की पहचान सुदृढ़ होगी, बल्कि नागरिकों की भावनाओं का भी सम्मान होगा। मेयर श्री शर्मा ने मुख्य नगर आयुक्त को तत्काल द्वार बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। जिस पर पार्षद सौरभ राज बेहड़ ने उनका आभार व्यक्त किया।

क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल में का वार्षिकोत्सव धूमधाम से सम्पन्न

रुद्रपुर। क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल, रुद्रपुर में "उड़ान; इस मिट्टी से आसमान तक" थीम पर एक भव्य, गरिमामयी एवं स्मरणीय वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जीवन की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देने वाला रहा। उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलमय दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को प्रेरणादायी स्वरूप प्रदान किया। इसके उपरांत प्रस्तुत सरस्वती वंदना ने सभागार को आध्यात्मिक चेतना एवं सांस्कृतिक आभा से आलोकित कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, के उपाध्यक्ष जय किशन, उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंध निदेशक, नारायण हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा

सेंटर डॉ. सोनिया अदलखा की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही विद्यालय की चेयरपर्सन श्रीमती फरजाना दोहादवाला एवं प्रधानाचार्या श्रीमती चित्रा शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नाटक "उड़ान; इस मिट्टी से आसमान तक" ने जीवन के संघर्ष, धैर्य और संकल्प की सशक्त अभिव्यक्ति करते हुए दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। इसके पश्चात नन्हे विद्यार्थियों की मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। ऊर्जावान भांगड़ा नृत्य ने सभागार को तालियों की गूंज और उल्लास से भर दिया। मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास, अभिनय क्षमता एवं कलात्मक कौशल की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए विद्यालय प्रबंधन को इस सफल, अनुकरणीय एवं प्रेरणास्पद आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती चित्रा शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सृजनशीलता, नेतृत्व क्षमता एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अंत में समस्त क्रिमसन परिवार ने "उड़ान की जीत का उद्घोष" करते हुए कार्यक्रम का भावपूर्ण समापन किया।